आपदा समाचार

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UP SDMA)

VOLUME – III

JAN 2025

LEARNING FROM PAST DISASTER
पूर्व आपदाओ से सीखना

FLOOD
बाढ़

FIRE
आग

LIGHTNING
वज्रपात

EARTHQUAKE
भूकम्प

COMMUNITY PREPAREDNESS
सामुदायिक तैयारी

EARLY WARNING SYSTEMS
पूर्व चेतावनी प्रणाली

EMERGENCY COORDINATION
आपातकालीन समन्वय

EMERGENCY RESPONSE TRAINING
आपातकालीन प्रशिक्षण

जागरूक नागरिक, सुरक्षित समाज

upsdma@gmail.com | @UP_SDMA | @sdmaup9884 | @UP SDMA Lucknow

लेफ्टिनेंट जनरल योगेन्द्र डिमरी
पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम., (से.नि.)
Lt Gen Yogendra Dimri
PVSM, AVSM, VSM (Retd)
उपाध्यक्ष / Vice Chairperson

उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
UP State Disaster Management Authority
बी–1 ब्लॉक, प्रथम तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
B-1 Block, First Floor, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand,
Gomtinagar, Lucknow-226010

सन्देश

प्रिय पाठकों,

आपदा समाचार पत्रिका के तृतीय संस्करण में आपका हार्दिक स्वागत है ।

इस संस्करण की थीम "Learning from Past Disasters" है। यह राज्य एवं जनपद के सभी विभागों की आपदा न्यूनीकरण हेतु की गयी कार्यवाही और जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है, साथ ही यह भी याद दिलाती है कि किसी भी आपदा की घटना में एक सीख है। आपदाओं की घटना के उपरान्त उसके प्रभाव को कम करने के बजाय, पूर्व की तैयारी और इससे मिलने वाले अनुभवों की जानकारियों से हम भविष्य में आपदा की घटना से होने वाले संभावित नुकसान को कम कर सकते हैं। इसी सीख को आत्मसात करते हुए हमें अपने विभागों, समुदायों, संस्थानों और संगठनों को अधिक सतर्क, संवेदनशील और सशक्त बनाना होगा।

इस संस्करण में हमने विभिन्न विभागों के अनुभवों, केस स्टडीज को संकलित किया है, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पूर्व आपदा से सीखे गए सबक हमारे नीति निर्माण, योजना और क्रियान्वयन में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

आशा है कि यह संस्करण आपको आपदाओं से जुड़ी नई जानकारी, बेहतर रणनीतियाँ और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करेगा, जो हमें और बेहतर तरीके से भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करेंगे।

शुभकामनाओं सहित

Editor
Dr. Kaneez Fatima
Project Director (Drought), UP SDMA

Technical Support
Mr. Prashant Kumar
Project Associate, UP SDMA

आपदा-मित्र : प्रथम उत्तरदाता

डॉ. सतीश कुमार (आई.पी.एस.)
सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0, लखनऊ

आपदा एक ऐसी घटना होती है जिससे जन-जीवन प्रभावित होता है और अधिक मात्रा में जनहानि, पर्यावरण और संसाधनों की क्षति होती है।

आपदाएँ दो प्रकार की होती हैं—

1. प्राकृतिक आपदाएँ : जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन आदि।
2. मानवजनित आपदाएँ : जैसे आग, केमिकल या न्यूक्लियर घटनाएँ, सड़क/रेल दुर्घटनाएँ आदि।

पहले आपदाओं से निपटने के लिए सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मदद ली जाती थी। लेकिन 2001 में गुजरात भूकंप और 2004 में सुनामी जैसी बड़ी आपदाओं के बाद, सरकार ने 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया। इसके तहत—

- राष्ट्रीय स्तर पर : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) का गठन हुआ।
- राज्य स्तर पर : राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) बनाए गए।

NDRF और SDRF विभिन राहत/बचाव के कार्य जैसे ढहे हुए भवनों से लोगों को निकालना, बाढ़, आग, बोरवेल दुर्घटनाओं और खतरनाक रसायनों से जुड़ी आपदाओं में मदद करते हैं। देश की भौगोलिक स्थिति एवं त्वरित कार्यवाही को ध्यान रखते हुए, सरकार ने "आपदा मित्र" और "आपदा सखी" नाम से स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने का फैसला लिया। इसके तहत एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड, सिविल डिफेंस, भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी गई, ताकि वे आपात स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर लोगों की मदद कर सकें।

उत्तर प्रदेश राज्य में आपदा मित्र परियोजना की शुरुआत मई 2016 में बाढ़ प्रभावित राज्यों में हुई। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बलिया के 200-200 स्वयंसेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 25 बाढ़ प्रभावित जिलों के 10,200 आपदा मित्रों और बाकी 48 जिलों से 100-100 होमगार्ड्स व स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण SDRF लखनऊ द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण की विशेषताएँ

- 12 दिन का कार्यक्रम, जिसमें थ्योरी, डेमो और प्रैक्टिकल सम्मिलित था।
- योग, पी.टी., खेल और प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग दी गई।
- आपदा से निपटने के लिए उपकरण (Responder Kit) और रू 5 लाख का जीवन बीमा प्रदान किया गया।
- रहने, खाने, चिकित्सा, बिजली, पानी, पुस्तकालय, जिम, खेल मैदान जैसी सुविधाएँ दी गई।

आपदा मित्रों की भूमिका

आपदा मित्र स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रचार-प्रसार, राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। इनकी बढ़ती आवश्यक्ता को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है।

प्रशिक्षण का विस्तार

उत्तर प्रदेश में 7 जनवरी 2022 को आपदा मित्र का पहला बैच शुरू हुआ। दूसरे चरण में 1 लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के तहत, उत्तर प्रदेश में 10,200 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण 36 बैचों में पूरा किया गया। इसके बाद 3767 होमगार्ड्स और 319 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया और शेष का प्रशिक्षण जारी है।

"आपदा मित्र परियोजना" आपदा प्रबंधन में एक क्रांति बन गई है, और भविष्य में इसकी आवश्यक्ता और भी बढ़ेगी।

फोटो 1 - आपदा मित्र प्रशिक्षण

फोटो 2 - आपदा मित्र द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम

सिटी हीट एक्शन प्लान

श्रीमती प्रियंका द्विवेदी
प्रोजेक्ट एक्सपर्ट (एग्रीकल्चर)

गर्मी से बचाव और सिटी हीट एक्शन प्लान

अत्यधिक गर्मी से स्वास्थ्य, आजीविका, कृषि, शिक्षा और सामान्य जीवन प्रभावित होता है। हीटवेव (लू) की चेतावनी बीमारियों की रोकथाम में मदद कर सकती है।

गर्मी का प्रभाव और तापमान रिकॉर्ड

जलवायु परिवर्तन के कारण हीटवेव की तीव्रता बढ़ रही है, जिससे खासतौर पर बुजुर्ग, रोगी और श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं। वर्ष 2024 में 21 जिलों का तापमान लगभग 45°C से अधिक पहुंचा।

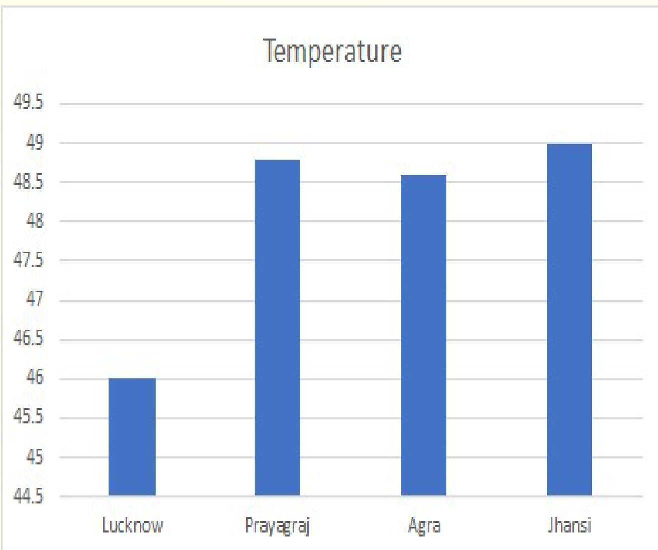

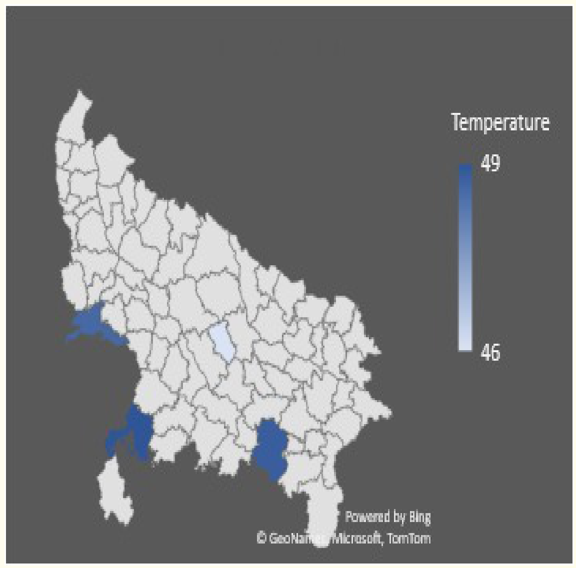

नोट – माह मई एवं जून 2024 में जनपद लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और झांसी (सर्वाधिक 49°C) में तापमान सर्वाधिक रहा
सिटी हीट एक्शन प्लान गर्मी से बचाव के लिए लखनऊ, आगरा और झांसी के लिए सिटी हीट एक्शन प्लान बनाया गया है। यह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यूनिसेफ और आई.आई.पी.एच., गाँधी नगर गुजरात संस्था के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया। इससे शहरों में गर्मी से बचाव हेतु शहरी योजना और नीतियों में सुधार किया जा सकेगा।

लखनऊ नगर निगम

लखनऊ नगर निगम अधिकारियों के साथ सिटी हीट ,क्शन प्लान विषय पर दूसरी बैठक दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 को आयोजित की गयी जिसमें (श्री राकेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी, श्री ललित कुमार एवं श्री पंकज कुमार अपर नगर आयुक्त, श्री संजीव प्रधान, पर्यावरण अभियन्ता, डॉ अमिताव श्रीवास्तव, ACMO स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ, तथा श्री अमर, आपदा विशेषज्ञ, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ, डॉ0 उर्वशी चन्द्रा, यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश, डॉ0 कनीज फातिमा, परियोजना निदेशक-सूखा, श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट-कृषि, एवं श्री प्रषांत शाही, प्रोग्रामर ग्रेड-2 उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा प्रो0 महावीर गोलेच्छा (IIPH) गांधीनगर से इसके अतिरिक्त अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण बैठक में उपस्थित थे।

आगरा नगर निगम

श्री अंकित खंडेलवाल (आई.ए.एस.), नगर आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 11 सितम्बर, 2024 को नगर निगम कार्यालय, आगरा में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें श्री सुरेंद्र यादव, अपर नगर आयुक्त आगरा, श्री शिवम कुमार, आपदा विशेषज्ञ, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से डॉ0 कनीज फातिमा, परियोजना निदेशक-सूखा, श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट-कृषि, एवं श्री प्रषांत शाही, प्रोग्रामर ग्रेड-2 तथा प्रो0 महावीर गोलेच्छा (IIPH) गांधीनगर से इसके अतिरिक्त अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण बैठक में उपस्थित थे।

झाँसी नगर निगम

श्री सत्य प्रकाश (आई.ए.एस.), नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय, झाँसी में दिनांक 10 सितम्बर, 2024 को बैठक आयोजित की यी, जिसमें श्री बिहारी लाल आर्य, महापौर, मो0 कमर, अपर नगर आयुक्त, श्री विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उप नगर आयुक्त झाँसी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से डॉ0 कनीज फातिमा, परियोजना निदेशक-सूखा, श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट-कृषि, एवं श्री प्रषांत शाही, प्रोग्रामर ग्रेड - 2 तथा प्रो0 महावीर गोलेच्छा (IIPH) गांधीनगर से बैठक में उपस्थित थे।

प्रयागराज नगर निगम

श्री दीपेन्द्र यादव एवं श्री अरविन्द कुमार राय, अपर नगर आयुक्त, की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय, प्रयागराज में दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 को बैठक आयोजित की गयी, जिसमें डॉ0 महेश कुमार नगर स्वास्थ्य अधिकारी, श्री उत्तम कुमार, पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से डॉ0 कनीज फातिमा, परियोजना निदेशक-सूखा, श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट-कृषि, एवं श्री प्रषांत शाही, प्रोग्रामर ग्रेड-2 तथा प्रो0 महावीर गोलेच्छा (IIPH) गांधीनगर से इसके अतिरिक्त अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीण बैठक में उपस्थित थे।

Management of State EOC & District EOC

श्री प्रवीन किशोर
प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर (ट्रेनिंग)

दिनांक : 28-29 अगस्त 2024
स्थान : जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, लखनऊ

उद्देश्य :

- आपातकालीन नियंत्रण केंद्रों के अधिकारियों को आधुनिक संचार तकनीकों की जानकारी देना।
- आपदा के दौरान बचाव और राहत कार्यो में बेहतर समन्वय बनाना।
- जिला और राज्य स्तर के आपातकालीन केंद्रों को मजबूत करना।

प्रतिभागी :

इस प्रशिक्षण में 64 जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों / राजस्व विभाग से अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आपदा विशेषज्ञ सहित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, स्वास्थ्य, सिंचाई, मौसम विभाग और अन्य एजेंसियों के 81 अधिकारी शामिल हुए।

प्रशिक्षण का संचालन :

- राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विशेषज्ञों ने आपदा प्रबंधन, राहत कार्यो और आधुनिक तकनीकों पर जानकारी दी।
- आंध्र प्रदेश और असम के अधिकारियों ने अपने राज्यों के आपातकालीन केंद्रों के संचालन का अनुभव साझा किया।
- मथुरा, श्रावस्ती और हापुड़ के विशेषज्ञों ने अपने जिले में अपनाई गई बेहतर प्रथाओं को बताया।
- उत्तर प्रदेश 112 सेवाओं की कार्यप्रणाली और टेक्नोलश्वजी आधारित आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी गई।

निष्कर्ष :

- उपाध्यक्ष महोदय, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के आपदा प्रबंधन केंद्रों को मजबूत करने पर जोर दिया।
- अधिकारियों ने फील्ड में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की।
- प्रशिक्षण से आपातकालीन संचालन, संचार तकनीक और राहत कार्यो को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए।

फोटो – प्रशिक्षण के दौरान समस्त प्रतिभागियों को प्रदेश में स्थापित उत्तर प्रदेश 112-आपात सेवाएं के प्रभारी अधिकारियों द्वारा इन्टीग्रेटेड टेक्नोलोजी इनेबिल्ड सिटीजन सेन्ट्रिक सर्विसेज (ITECCS) की अवधारणा, संचालन, कार्यप्रणाली तथा प्रबन्धन से अवगत कराया गया।

आपदा समाचार
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

India Disaster Resource Network (IDRN)

Shri Prashant Shahi
Programmer Grade-2

The India Disaster Resource Network (IDRN) is a web-based platform for managing the inventory of equipment, skilled human resources and critical supplies for emergency response. It was Initiated by Ministry of Home Affairs (MHA) in 2004 under the GOI - UNDP Disaster Risk Management (DRM) Programme, to build up a systematic inventory of equipment and skilled human resources so that disaster managers can find the location and details of the resources for immediate response. National Institute of Disaster Management (NIDM), Ministry of Home Affairs, Government of India, has been managing the IDRN Portal since June 2008.

The primary focus is to enable the decision makers to access equipment and human resources required to combat any emergency.

As per PM's 10-point agenda No.5 "Leverage technology to enhance the efficiency of disaster risk management efforts."

"Technology must be strategically leveraged to improve the efficiency and effectiveness of disaster risk management." This requires use of technology in resource planning, e.g., India Disaster Resources Network (IDRN), creation of e-platform to map expertise and resources on highly specialized aspects of disaster response and to increase the efficacy of early warning mechanisms.

Data Collection Process

- The data collection formats are intended to be filled up by the line departments/ agencies/ organizations and the whole exercise will be coordinated by the District Authority (DM).

- The format needs to be sent to all line departments / agencies from the district administration and need to be collected within a week or on particular time limit period. Then the data entry should be done at the district level under the DM's authority.

Form & 1	(Department or Agency Details)
Form & 2A	(For all types of equipment only)
Form & 2B	(For all types of skilled human resource only)
Form & 2C	(For all types of critical supplies only)

Role of UPSDMA in Ensuring Safety and Resilience at Maha Kumbh 2025

Shri Chander Kant
Project Expert (Flood Control)

Emergency Communication: Cell Broadcast System Deployment

A major initiative is the deployment of the Cell Broadcast System developed by C-DOT to deliver real-time emergency alerts across the Maha Kumbh Mela area. This system is pivotal for rapid information dissemination in crisis scenarios.

- Internal testing is currently being conducted across Prayagraj and nearby districts and will continue up to the Mela.
- A comprehensive system test is scheduled for January 4, 2025, aligned with a mock drill in the Mela zone.
- A review meeting with the C-DOT team and concerned officials is proposed on the same day to assess the system's functionality and integration with the Mela's emergency response plan.

Strategic Planning and Risk Assessment

The Uttar Pradesh State Disaster Management Authority (UP SDMA) is leading the disaster preparedness efforts, which include:

- Conducting a Hazard Risk Vulnerability and Capacity Assessment (HRVCA).
- Drafting the Maha Kumbh 2025 Disaster Management Plan.

These efforts are critical to identifying risks and allocating resources effectively.

Volunteer and Departmental Training Initiatives

Training is a cornerstone of preparedness, targeting thousands of volunteers from Civil Defense, Aapda Mitra, NCC/NSS, and Home Guards.

- Training is scheduled to be completed by December 20, 2024.
- In-house training for key departments such as police (armed and traffic), railways, communication, home guards, and health is already underway.
- Behavioral and Crowd Management Training for police personnel has commenced.

Exercises and Simulation Drills

Two major exercises are planned to evaluate and refine emergency response strategies:

- Table Top Exercise (TTEx): Tentatively on November 29, 2024.
- Mock Exercise (ME): Scheduled for December 12, 2024, in Prayagraj.

These drills will test coordination, decision-making, and operational readiness across all agencies.

आपदा जोखिम प्रबंधन में सोशल मीडिया की भूमिका

श्री प्रशान्त कुमार
प्रोजेक्ट एसोसिएट (आई. सी. एण्ड ई. एम.)

आज के डिजिटल समय में सोशल मीडिया आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster Risk Management) के लिए एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। इसके माध्यम से आपदा से पूर्व, दौरान एवं आपदा के बाद सूचनाओं के आदान-प्रदान में विशेष सहायता मिलती है। वर्तमान समय में निम्नलिखित रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है :-

1. **अर्ली वार्निंग चेतावनी और सूचना प्रसार** : सोशल मीडिया के माध्यम से अर्ली वार्निंग एजेंसी, सरकारें और अन्य संगठन तत्काल सूचना और चेतावनियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जा रही है, जिससे आम जन मानस को सुरक्षा उपायों की जानकारी जल्दी मिल सके ।
2. **रीयल-टाइम अपडेट्स** : किसी भी आपदा के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी वर्तमान स्थिति, मौसम एवं भौगोलिक जानकारी साझा करने से, आपदा की गंभीरता और असर का अनुमान लगाया जा सकता है।
3. **संचार का माध्यम** : आपदा के दौरान प्रशासन और आम जनता के बीच संचार बनाए रखने में सोशल मीडिया मदद करता है।
4. **सहायता और पुनर्वास** : सोशल मीडिया के माध्यम से राहत कार्यो के लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं, जैसे दान हेतु स्वयंसेवी संस्थानों से संपर्क किया जा सकता है।
5. **फेक न्यूज का खंडन** : सोशल मीडिया पर आपदा के दौरान गलत अफवाहों को रोकने के लिए सही जानकारी और स्रोत प्रदान किए जाते हैं।
6. **डाटा विश्लेषण** : सोशल मीडिया से मिली जानकारी का विश्लेषण कर त्वरित और सही निर्णय लिया जा सकता है।
7. **जागरुकता अभियान** : सोशल मीडिया के माध्यम से आपदा के बारे में जागरुकता एवं जानकारी फैलाने के लिए अभियान चलाए जा सकते हैं।

निष्कर्ष : सोशल मीडिया आपदा जोखिम प्रबंधन में सूचना प्रसार, संसाधन जुटाने और लोगों को जागरुक करने के लिए एक प्रभावशाली साधन है, जो स्थिति की निगरानी और निर्णय लेने में भी सहायक है। वर्तमान समय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधी जानकारी एवं उपायों को आम जनमानस के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सोशल मीडिया से निम्नलिखित लिंक से जुड़ सकते है : -

1- https://x-com/up_sdma
2- https://www-youtube-com/@sdmaup9884
3- https://www-facebook-com/UPStateDisasterManagementAuthority

आपदा न्यूनीकरण में पुलिस दूरसंचार की भूमिका

श्री सुनील कुमार सिंह (आई.पी.एस.)
महानिरीक्षक / निदेशक (पुलिस दूरसंचार)

धटना 1 – बाराबंकी शहर के बीच से बहने वाला जमुरिया नाला, रेठ नदी से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2023 में भारी वर्षा के कारण नाला और नदी में भीषण बाढ़ आ गई, जिससे आधा शहर जलमग्न हो गया था। नाले के किनारे बसे घरों और बाजारों में पानी भर गया, जिससे जन-धन हानि का खतरा बढ़ गया था।

धटना 2 – गोंडा जिले के थाना मोतीगंज क्षेत्र में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या-15904 दिनांक 18-07-2024) की दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की।

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

- बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
- आपदा नियंत्रण कक्ष (DCR) को सक्रिय कर 24/7 निगरानी शुरू की गई।
- दूरसंचार विभाग की टीम को वायरलेस सेट सहित धटनास्थल पर भेजा गया।
- हैंडहेल्ड सेट और मोबाइल आरटी सेट्स के जरिए संचार व्यवस्था को मजबूत किया गया।
- राहत कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को हैंडहेल्ड सेट उपलब्ध कराए गए।
- महत्वपूर्ण सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान कर राहत और बचाव कार्य को तेज किया गया।

निष्कर्ष –

1- सुदृढ़ संचार प्रबंधन और मानक प्रक्रिया का पालन करने से बाढ़ से हुए नुकसान को कम किया जा सका और राहत कार्यो को समय पर और प्रभावी ढंग से किया गया, जिससे आपदा के प्रभाव को कम किया जा सका।

2- वायरलेस संचार एवं हैण्डहेल्ड सेट किसी भी आपदा के दौरान संचार एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहायक है।

फोटो- बाढ़ आपदा एवं रेल दुर्घटना के दौरान संचार हेतु वायरलेस संचार एवं हैण्डहेल्ड सेट का उपयोग

Flood Rescue/Evacuation Operations

NDRF 11th Bn Varanasi

Incident Overview - The District Administration of Bahraich received information about villagers stranded in floodwaters, particularly in Village Chahalwa, Tehsil Mihinpurwa, Thana Sujauli, District Bahraich. In response, Team 11B, led by Inspector Dhirendra Singh, along with 2 Sub & Inspectors and 27 other rescuers, was deployed from Prathmik Vidyalaya Tandwa Mahant, Sitadwar at 2215 hours to conduct the rescue operation,The team navigated through dense forests of Katarnia Ghat Wildlife Sanctuary covering approximately 160 kilometers during the night. They reached the incident site at 0227 hours. Due to inaccessible terrain, the boat and outboard motor (OBM) had to be manually transported 800 meters from the road to the flood & affected area.

Rescue Operation - Despite challenging conditions, the team assembled the boat and OBM and immediately began search and rescue operations in the strong flood currents. The operation was hindered by uprooted trees and potential crocodile threats, as reported by locals. However, the rescuers displayed exceptional determination and professionalism throughout the mission.

Outcome- A total of 89 villagers (41 males, 48 females) were rescued from the Ghaghra Basin (near Kailash Puri Barrage) and safely evacuated to a secure location near Village Chahalwa, PS Sujauli, Tehsil Mihinpurwa, District Bahraich. The team's morale remained high, and their dedication was acknowledged by both the villagers and the district administration.

Recognition & Appreciation -

- Senior officers commended the efforts of Team 11B for their commitment and bravery.
- The rescuers were rewarded by supervisory staff for their tireless dedication and continuous efforts.

Lessons Learnt - To improve future flood response and mitigation the following key measures should be considered:

- Implement an advanced early warning system for flood prone areas
- Strengthen flood control infrastructure such as dams levees and stormwater management systems
- Enhance community awareness through Community Action Programs (CAP) and Community & Based Programs (CBP), promoting emergency preparedness and safe evacuation practices.
- Encourage resilient housing design in flood & affected areas.

NDRF 11th Bn Varanasi Team rescued 89 villagers from floodwaters of Ghaghra Basin and safely evacuated them to a secure location.

बांसमंडी अग्निदुर्घटना

श्री दीपक शर्मा (सी.एफ.ओ.)
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, कानपुर नगर

आग लगने की घटना

स्थान : बांसमंडी क्षेत्र, थाना अनवरगंज, कानपुर / दिनांक व समय : 31 मार्च 2023, प्रातः 01:34 बजे

आग लगने का कारण : ए.आर. टावर में इलेक्ट्रिक शार्ट सर्किट

आग फैलने के कारण :

- आग की सूचना देरी से मिलना तथा फायर फाइटिंग सिस्टम की अनुपलब्धता
- भवनों में अग्निरोधी उपायों की कमी एवं तेज आंधी के कारण आग का तेजी से फैलना तथा निकास मार्गो का अवरुद्ध होना

अग्निशमन, राहत एवं बचाव कार्य :

- 120 घंटे, 5 दिन तक लगातार आग बुझाने का कार्य चला।
- 53 फायर टेंडर, 3 हाइड्रोलिक प्लेटफश्वर्म व 500 से अधिक अग्निशमन कर्मियों ने आग बुझाने में सहयोग किया।
- 475 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
- 250 दुकानों को जलने से बचाया गया, जिससे करोड़ों की संपत्ति सुरक्षित रही।
- SBI के महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाकर रूम व करोड़ों की करेंसी सुरक्षित बचाई गई।
- ऊपरी मंजिलों पर फंसे 25 लोगों को BA सेट की मदद से सुरक्षित निकाला गया।
- आग के चारों ओर बैरियर बना कर आगे बढ़ने से रोका गया, जिससे लकड़ी/फर्नीचर गोदाम सुरक्षित रहे।

बचाव कार्य में चुनौतियाँ :

- निकास मार्गो की कमी और वेंटिलेशन का अभाव तथा भवनों में अग्निरोधी उपायों की अनुपलब्धता।
- फायर हाइड्रेंट व रिजर्व वाटर टैंक की कमी एवं संकरी गलियों और आसपास घनी आबादी का होना।
- कपड़ों के बाजार के कारण बार-बार आग लगना तथा 5 दिनों तक चलने वाले अश्वपरेशन में संसाधनों का प्रबंधन।

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम :

- अग्निसुरक्षा और विद्युत सुरक्षा ऑडिट एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- संवेदनशील स्थानों पर फायर हाइड्रेंट व पानी की टंकियों की स्थापना।
- आधुनिक अग्निशमन वाहनों और उपकरणों की उपलब्धता।
- संवेदनशील क्षेत्रों में फायर फाइटिंग मोटरसाइकिल गश्त।

निष्कर्ष : यह घटना दर्शाती है कि समय पर प्रतिक्रिया, बेहतर संसाधन और सही सुरक्षा उपायों से बड़ी क्षति को रोका जा सकता है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन आवश्यक है।

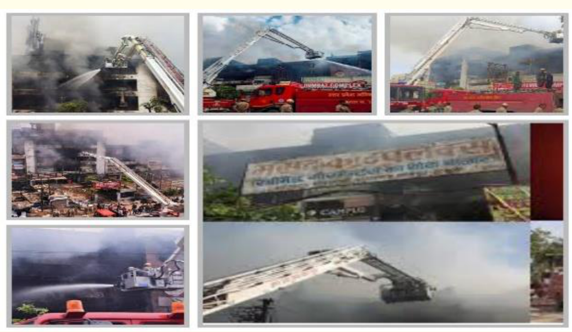

फोटो - अग्निशमन विभाग द्वारा राहत बचाव का कार्य

फोटो - सुरक्षित लोगों की निकासी का कार्य

जनपद सुलतानपुर में इमरजेंसी एसेंसिअल रिसोर्स रिजर्व किट की उपयोगिता

श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना (आई.ए.एस.), जिलाधिकारी
श्री एस0 सुधाकरन, अपर जिलाधिकारी(वि./ रा.)
श्री आदित्य प्रकाश जायसवाल, जिला आपदा विशेषज्ञ

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा बचाव किट उपलब्ध करायी गयी है। इस किट में इन्फ्लेटेबल बोट, ओबीएम मशीन सहित 30 आधुनिक उपकरण हैं, जो आपदा और आपातकालीन स्थितियों में बचाव कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम :
जिलाधिकारी के निर्देश पर बाढ़, आग, सर्पदंश और डूबने जैसी आपदाओं से बचाव के लिए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया।

- स्थान : कलेक्ट्रेट सभागार, सुल्तानपुर
- सहयोग : राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), अयोध्या
- प्रतिभागी : तहसीलदार, राजस्व लेखपाल, नाविक और गोताखोर

प्रशिक्षण में शामिल बातें :

- आपदा बचाव किट के उपकरणों का सही उपयोग
- आपदा से पहले सतर्कता और तैयारी का महत्व
- ग्रामीण स्तर पर आपदा राहत चौपाल आयोजित करने के निर्देश
- इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पांडर की भूमिका और जिम्मेदारी

निष्कर्ष : जनपदों को उपलब्ध करायी गयी इमरजेंसी एसेंसिअल रिसोर्स रिजर्व किट के उपयोग से समय पर सतर्कता और सही प्रशिक्षण से जनधन की हानि को कम करना।

फोटो – राज्य आपदा मोचन बल द्वारा जनपद सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों जिसमें तहसीलदार, राजस्व लेखपाल तथा नाविक और गोताखोर को EERR किट के उपयोग की जानकारी दी।

जनपद इटावा में भारी वर्षा की चेतावनी के दौरान त्वरित आपदा रिस्पॉन्स का कार्य

श्री अवनीश राय (आई.ए.एस.) जिलाधिकारी
श्री अभिनव रंजन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (वि./ रा.)
श्री अवनीश दूबे, जिला आपदा विशेषज्ञ

1. घटना का विवरण – जर्जर हवेली की दीवार गिरने का खतरा।
2. प्रभावित क्षेत्र – ग्राम मुकटपुर, ब्लश्वक महेवा, तहसील भरथना, जिला इटावा।
3. **प्रभावित परिवार –**
    - विमला पत्नी मुन्नू
    - सुमन पत्नी रामप्रकाश
    - संजू, अमित, प्रदीप, मुकेश (संतान)
    - राजकुमार पुत्र रामकुमार
    - गोलू और शिल्पी (बच्चे)

घटना का विवरण

- दिनांक 11.09.2024 की रात हुई भारी बारिश के कारण हवेली की दीवारों में दरारें आ गई और उनके गिरने का खतरा बढ़ गया।
- क्षेत्रीय लेखपाल ने स्थिति का जायजा लेकर तहसील प्रशासन को सूचना दी।
- तहसीलदार के निर्देश पर भवन स्वामियों को नोटिस देकर तुरंत आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।
- जर्जर हवेली के पास रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थान पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया।
- भवन स्वामियों ने खुद ही कमजोर दीवारों को गिरवा दिया, जिससे हादसे को टाला जा सका।

बचाव कार्य और प्रशासन की तत्परता

- प्रशासन की सतर्कता से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया।
- यदि परिवार वहां मौजूद रहता, तो गंभीर हादसा हो सकता था।
- भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और समय रहते उचित कार्रवाई करने का संकल्प लिया।

फोटो – पुरानी जर्जर भवन हवेली के समीप वर्ती परिवार को सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा शेल्टर होम में प्रतिस्थापित किया गया।

लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर में ध्वस्त इमारत में खोज एवं बचाव सम्बन्धी कार्य

श्री सूर्य पाल गंगवार (आई०ए०एस०) जिलाधिकारी
श्री राकेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
श्री अमर सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ

लखनऊ में तीन मंजिला इमारत (हरमिलाप बिल्डिंग) गिरने की घटना

तारीख : 07.09.2024

स्थान : ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ

घटना का विवरण : लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक तीन मंजिला व्यवसायिक इमारत अचानक गिर गई। उस समय इमारत में कई लोग मौजूद थे।

बचाव कार्य :

- घटना की सूचना मिलते ही मंडलायुक्त रोशन जैकब, जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार, अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह,
- उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और आपदा विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे।
- पुलिस, अग्निशमन विभाग, एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. की टीमें तुरंत बचाव कार्य में जुट गई।
- विशेष उपकरणों की मदद से मलबे में फंसे लोगों को खोजा गया।
- रात 10:00 बजे तक रेस्क्यू आपरेशन चला।

घायलों और मृतकों की स्थिति :

- 08 लोगों की मौत हो गई।
- 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें लोकबंधु और अवध अस्पताल में भर्ती कराया गया।
- कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

सहायता राशि :

- मृतकों के परिजनों को रु 2 लाख की आर्थिक सहायता दी गई।
- घायलों को रु 50,000 की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रदान की गई।

प्रशासन की तत्परता :

प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन दल, एन.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ. और रोबोज डॉटइन टेक प्रा. लि. के मिलिंद राज की मदद से त्वरित बचाव कार्य किया गया, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी।

फोटो – ट्रांसपोर्ट नगर में जिला प्रशासन एवं राज्य आपदा मोचक बल द्वारा राहत बचाव का कार्य

कुशीनगर बाढ़ बचाव कार्य वर्ष 2024

श्री विशाल भारद्वाज (आई0ए0एस0), जिलाधिकारी
श्री श्री वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
श्री रवि राय, जिला आपदा विशेषज्ञ

दिनांक : 06.07.2024
समय : दोपहर 1:00 बजे

स्थिति :
बाल्मिकी नगर बैराज से 2,03,800 क्यूसेक पानी बड़ी गंडक नदी में छोड़ा गया। हाइड्रोलॉजी विभाग, नेपाल के अनुसार, भारी बारिश और देवघाट बैराज में जलभराव (4,00,000 लाख क्यूसेक) के कारण जलस्तर बढ़ने की संभावना थी।

प्रशासन की कार्रवाई :

आपदा विशेषज्ञ ने स्थिति का विश्लेषण कर जिलाधिकारी को तुरंत सूचित किया।
जिलाधिकारी ने एसडीआरएफ टीम की तैनाती के लिए राहत आयुक्त को पत्र भेजा।
उपजिलाधिकारी खड्डा और तमकुहीराज को संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों में मुनादी (घोषणा) और पीए सिस्टम से लोगों को सतर्क करने का निर्देश दिया।
बाढ़ चौकियों और राहत शिविरों को तुरंत सक्रिय किया गया।

सतर्कता और जागरूकता :

मंदिर, मस्जिद और मुनादी के माध्यम से लोगों को जलस्तर बढ़ने की सूचना दी गई।
खड्डा तहसील पर विशेष निगरानी रखी गई, क्योंकि यह क्षेत्र 6–7 घंटे में प्रभावित हो सकता था।
इस तरह समय पर सतर्कता और बचाव कार्यों से लोगों को सुरक्षित किया गया।

फोटो- जनपद कुशीनगर के ग्रामों में तथा मंदिर, मस्जिद में बाढ़ के दौरान मुनादी के माध्यम से लोगों को जलस्तर बढ़ने की सूचना दी गई।

गोरखपुर – आपदा मित्रों/सखियों ने संभाली ई0ओ0सी0 की कमान

श्री कृष्णा करुणेश, (आई.ए.एस.), जिलाधिकारी
श्री विनीत कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी(वि./रा.)
श्री गौतम गुप्ता, जिला आपदा विशेषज्ञ

भूमिका :

राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित ''केन्द्र पुरोनिधानित आपदा मित्र परियोजना'' के अंतर्गत वर्ष–2017 में जनपद–गोरखपुर के 200 आपदा मित्र/सखी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, वाराणसी, उ0प्र0 के नेतृत्व में बाढ़ के दौरान स्वयं को सुरक्षित रखते हुए जनसमुदाय को सुरक्षित रखने विषयक प्रशिक्षण प्राप्त किया। तदोपरांत जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण लखनऊ, राहत आयुक्त कार्यालय उ0प्र0 शासन तथा यूनिसेफ, उ0प्र0 आदि विभिन्न विभागों/संगठनों के सहयोग से समय–समय पर आपदा मित्रों/सखियों के ''क्षमता संवर्द्धन'' हेतु कार्य किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जनपद के विभिन्न ग्रामों की ''ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण योजना'' का निर्माण, विद्यालयों में ''स्कूल हजार्ड हंट'' प्रशिक्षण कार्यक्रम मय ''विद्यालय सुरक्षा योजना'' निर्माण कार्य तथा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन किया गया। आपदा मित्रों/सखियों ने ''कोविड–19'' के दौरान भी सक्रिय रुप से जनसमुदाय को जागरूक करने तथा राहत वितरण आदि में सहयोग प्रदान किया।

जनपद की संवेदनशीलता :

गोरखपुर बहु आपदा प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभिषिका के साथ–साथ व्यापक रूप में अग्निकाण्ड की घटनाएं, सर्पदंश, वज्रपात, आंधी–तूफान, डूबने से मृत्यु आदि आपदाएं घटित होती हैं, जिसके न्यूनीकरण में आपदा मित्रों/सखियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

बाढ़–2024 एवं जिला इमरजेंसी आपरेशन सेंटर :

शासन के निर्देशानुसार बाढ़ के दौरान त्वरित राहत व बचाव कार्य के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय 24x7 इमरजेंसी आपरेशन सेंटर (ई0ओ0सी0) का संचालन किया जाता है। ई0ओ0सी0 के सफल संचालन हेतु 03 पालियों में (प्रत्येक पाली 08 घण्टा) कर्मचारियों की तैनाती की जाती है। उक्त कर्मचारियों का यह दायित्व होता है कि प्रत्येक तहसील से बाढ़ के दृष्टिगत किये जा रहे कार्यो से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करें, उन्हें संकलित कर जनपद स्तर से शासन को प्रेषित करें, घटित घटनाओं का विवरण एकत्र करें, मीडिया में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों से किये जा रहे कार्यो का विवरण एकत्र करें तथा नदी जलस्तर व मौसम पूर्वानुमान आदि के आधार पर ''फ्लड बुलेटिन'' जारी करें।

आपदा मित्रों/सखियों की तैनाती :

शासन के निर्देशानुसार 24x7 इमरजेंसी आपरेशन सेंटर (ई0ओ0सी0) संचालन हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, किंतु विभागों में सीमित मानव संसाधन होने के कारण कर्मचारियों की तैनाती में कठिनाईयां उत्पन्न होती है। उक्त के दृष्टिगत विगत कई वर्षो से ई0ओ0सी0 के अंतर्गत होमगार्ड्स व पीआरडी जवानों की तैनाती की जाती रही है। वर्ष–2024 में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा–28(3) Any person associated as an expert with any committee or sub&committee constituted under sub&section (I) may be paid such allowances as may be prescribed by the State Government के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के स्वीकृति के आधार पर प्रशिक्षित किये गये आपदा मित्रों/सखियों ने दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 08 नवम्बर, 2024 तक जिला इमरजेंसी आपरेशन सेंटर (ई0ओ0सी0) की कमान संभाली। संबद्ध किये गये आपदा मित्रों/सखियों को जिला युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय से संबद्ध पी.आर.डी. जवानों को दिये जाने वाले मानदेय रू0 395.00 प्रति दिवस के आधार पर भुगतान भी किया गया।

आपदा मित्रों/सखियों द्वारा संपादित कार्य :

बाढ़काल के दौरान आपदा मित्रों/सखियों ने तहसीलों एवं विभागों से समन्वय स्थापित कर सूचनाओं का एकत्रीकरण, सूचनाओं का प्रेषण, दस्तावेजीकरण, नदी जलस्तर की मानीटरिंग, मीडिया में प्रकाशित खबरों का सत्यापन कार्य, वायरलेस का संचालन आदि अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपादित किये जो कि सराहनीय रहे। बाढ़ के साथ-साथ माँ दुर्गा व माता लक्ष्मी की प्रतिमा विसर्जन, छठ पर्व आदि अन्य नदी घाट से जुड़े कार्यो से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण ई0ओ0सी0 के माध्यम से संपादित किया। आपदा मित्रों/सखियों ने यह साबित किया कि यदि उन्हें अवसर प्राप्त हों तो ''समुदाय आधारित आपदा न्यूनीकरण'' संबंधित कार्यो में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

आपदा मित्रों के अनुभव :

मेरा यह पहला अनुभव है और ई0ओ0सी0 में ड्यूटी करते हुए मुझे विभागों की संरचना तथा उनके द्वारा आपदा के दृष्टिगत किये जाने वाले कार्यो के संबंध में जानकारी प्राप्त हुयी। मैं उक्त जानकारी को समुदाय स्तर पर साझा एवं प्रसारित करुंगी, जिससे कि लोगों को त्वरित सहायता प्राप्त हो सके। **कु0 ज्ञान्ती, आपदा सखी, बांसगांव**

आपदा प्रतिउत्तर कार्य में पुलिस, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, विद्युत, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आदि कई विभागों की भूमिका है, जिसके संबंध में ड्यूटी के दौरान ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कि मेरे भविष्य के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगा। **कृष्णा कुमार, आपदा मित्र, सदर**

फोटो- जनपद गोरखपुर में बाढ़ के दौरान जिला इमरजेंसी आपरेशन सेंटर (ई0ओ0सी0) में तैनाती की गयी।

बलिया बाढ़ राहत और चिकित्सा सहायता

डॉ. विजय पति द्विवेदी, मुख्य चिकित्साधिकारी
डॉ. अभिषेक मिश्रा, जिला सर्विलांस अधिकारी
श्री शैलेन्द्र पाण्डेय, फार्मासिस्ट, संचारी रोग नियंत्रण इकाई

दिनांक 18 सितंबर 2024 को रात्रि 2:00 बजे, बलिया जनपद के बैरिया तहसील में NH-31 का एक हिस्सा बाढ़ में बह गया, जिससे आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए। यह मार्ग बलिया (उत्तर प्रदेश) और छपरा (बिहार) को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक मार्ग है।

तत्काल चिकित्सा सहायता

- स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संपर्क कर चिकित्सकों की टीम को दवाओं के साथ भेजा।
- प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाए गए और जरूरतमंदों को दवाइयां वितरित की गईं।
- दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा न मिलने की सूचना मिलने पर मोबाइल मेडिकल टीमें भेजी गईं।

घर-घर जाकर चिकित्सा सेवा

- चाँद दीयर इलाके में कुछ बीमार बुजुर्ग और महिलाएं घरों में फंसे थे, जिनके लिए नाव की व्यवस्था कर स्वास्थ्य टीमें उनके पास पहुंचीं।
- कुछ लोग छतों पर रहने को मजबूर थे, इसलिए रेड क्रश्वस द्वारा वितरित भोजन के साथ दवाइयां भी रस्सी के माध्यम से पहुंचाई गईं।
- प्रशासन और रेड क्रश्वस के सहयोग से लोगों को सेनेटरी पैड, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा सेवाएं दी गईं।

सीख और भविष्य की योजना

- भविष्य में, प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से नाव के माध्यम से घर-घर चिकित्सा सुविधा देने की योजना बनाई गई।
- यह अभिनव प्रयास स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की समर्पित सेवा का उदाहरण बना।

बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आयी रेड क्रास सोसाइटी

बलिया। जिलाधिकारी/अध्यक्ष इंडियन रेड क्रास सोसाइटी बलिया के निर्देशानुसार व चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में इंडियन रेड क्रास सोसाइटी बलिया की टीम ने चांददियर में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित किया। इस दौरान रेड क्रास टीम ने प्रभावित लोगों को नाव के सहारे पानी में जलमग्न उनके दरवाजे तक पहुंच कर तिरपाल व ब्रेड के साथ-साथ संक्रामक बीमारियों से बचने हेतु आवश्यक दवाई भी वितरित किया। डीएसओ व संरक्षक सदस्य रेड क्रास डा. अभिषेक मिश्रा ने कहा कि रेड क्रास सोसायटी जरूरतमंद लोगों के हर सुख-दुख में सहारा बनकर खड़ी रहती है। वर्तमान समय में बाढ़ की भयानक विभीषिका के बीच हम सभी मानव धर्म का निर्वाहन करते हुए लोगों की मदद हेतु कार्य कर रहे हैं। संरक्षक सदस्य सरदार सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि रेड क्रास पीड़ित व असहाय लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का पुण्य कार्य हमेशा से करती आ रही है। चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि रेड क्रास मानव सेवा के अपने मूल स्वभाव के अनुरूप ही बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। उन्होंने साथ ही जनपद के सभी सक्षम लोगों और संस्थाओं को भी प्रभावित लोगों की-मदद के लिए अपील किया। इस मौके पर शैलेंद्र पाण्डेय, नंदिनी, नायब तहसीलदार रोशन सिंह, ओमकार सिंह, पंकज कुमार, जितेंद्र सिंह, जयशंकर सिंह आदि उपस्थित रहे।

फोटो- जनपद बलिया में बाढ़ से घिरे लोगों को राज्य आपदा मोचन बल द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया एवं आवश्यक दवाइयाँ और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया।

Impact of 2024 Flood on Communities

Shri Ranjit Ranjan,
Disaster Expert, DDMA Basti

Introduction

In 2024 Basti district recorded, flood for one month because of heavy monsoon rains and water releases from Nepal. The disaster disproportionately affected poor rural communities, especially those that were dependent on agriculture, fishing, and informal employment. This case study examines how the communities adapted the challenges brought about by the flood with few resources and traditional knowledge-displaying resilience, adaptability, and solidarity against adversity.

Background

Basti district has a varied socio-economic profile, with most of the population being involved in agriculture, fishing, and casual labor. These populations tend to reside in flood-affected areas and rely extensively on local natural resources for their livelihood. The floodwaters flooded homes, damaged crops, and interfered with everyday life, leading to a critical need for effective, locally led responses and survival mechanisms.

Immediate Response to the Flood

As floodwaters increased, the District Disaster Management Authority (DDMA), led by the ADM (F/R) and disaster management specialists, undertook immediate evacuations. Households put safety first, moving to higher ground and temporary camps. Locals utilized their knowledge of territory to determine safe locations—such as elevated ground and relatives' homes in unaffected areas.

Local community leaders and volunteer groups soon mobilized teams to identify needs and coordinate rescue efforts. Word-of-mouth and face-to-face communication were crucial in sharing information regarding safety paths and shelter facilities. Elders disseminated coping strategies gleaned from previous flooding, reiterating the need for solidarity and preparedness.

Resource Mobilization

Though faced with limited resources, the targeted communities were great in unity and resourcefulness. Families rallied around each other and shared food, water, and basic supplies. Women took charge, mobilizing community kitchens that served meals from temporary shelters, making sure every individual was fed. Food distribution from the Rahat office proved vital in helping augment local initiatives.

The locals also constructed temporary shelters with bamboo, thatch, and tarpaulin material supplied by the tehsil. Their understanding of local materials and traditional construction practices made the structures provide immediate relief and reinforce a sense of cooperation.

Indigenous Knowledge and Adaptation

Traditional knowledge was important in enabling communities to cope. Local fishermen employed traditional methods to harvest fish swept by the floodwaters, contributing to food stocks during a period when market access was restricted.

Community Solidarity and Support Networks
Community cohesion was perhaps the strongest reaction to the disaster- Neighbors assisted each other with reconstruction pooled resources and formed informal networks to care for children and the elderly so others could concentrate on recovery.

The local leaders were central in coordinating the assistance interfacing with authorities and aid agencies and seeing that communities in their areas received the required support such as food] medical relief and construction materials. This collective action assisted in filling the gaps where institutional response was slow or inadequate.

Long-Term Strategies and Building Resilience
Following the flood communities started thinking about long & term resilience strategies- Community meeting were organized to deliberate on flood mitigation strategies like enhanced drainage and the development of flood barriers and to campaign these options with local government officials.

Skill enhancement workshops were organized to support customary livelihoods and others sources of income. Fishermen learned sustainable practices and cooperative models for selling their products.

Conclusion
The 2024 Basti district flood evidenced the vulnerabilities of exposed communities- Their mass response however also brought to light the resilience of community ties the worth of traditional knowledge and the force of collective support. Through solidarity adaptive practices and sharing resources such communities not only survived the crisis but set a precedent for a more resilient future. Their example highlights the necessity of inclusive community based disaster management practices that incorporate local wisdom and capacity in the pursuit of climate resilience.

Uttar Pradesh

State Disaster Management Authority

(UP SDMA)

Address : B-1 Block, PICUP Bhawan, PICUP Building Road, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh, 226010

Website : https://upsdma.up.nic.in Email : upsdma@gmail.com Phone : 0522-2306882

For more information, visit our web at www.upsdma.up.nic.in